सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

माननीय श्री. सी. पी. राधाकृष्णन

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

०३ मार्च २०२५

मान्नीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण,

वर्ष २०२५ में, राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है ।

२. मेरी सरकार, राज्य के लोगों की सेवा में राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर, भगवान बिरसा मुंड़ा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और कई अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों के उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है ।

३. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद सुलझाने के लिए वचनबद्ध है और इस विवाद को सुलझाने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गयी याचिका में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विख्यात अधिवक्ताओं को नियुक्त किया गया है । मेरी सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले मराठी-भाषी लोगों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और विविध अन्य कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है ।

४. महाराष्ट्र, सीधे विदेशी निवेश करने के लिए पसंदीदा राज्य है और देश के कुल सक़ल घरेलु उत्पाद में महाराष्ट्र १४ प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जो देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में से एक है ।

मेरी सरकार ने, जनवरी २०२५ में, स्विट्झर्लंड के दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में ६३ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ लगभग १५ लाख ७२ हजार करोड़ रुपयों की निवेश राशि के सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं । इससे राज्य में १५ लाख से अधिक रोज़गार के अवसर निर्माण होंगे ।

५. मेरी सरकार ने, राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर निर्माण करने के लिए विभिन्न उद्योगों को लगभग ५००० करोड़ रुपयों का निवेश प्रोत्साहन अनुदान वितरित करने की योजना बनायी है ।

६. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के ज़रिए राज्य में औद्योगीकरण को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए लगभग ३,५०० एकड़ औद्योगिक भूखंड को आवंटित करने का निर्णय लिया है ।

७. मेरी सरकार ने, औद्योगिक भूमि की बढ़ती माँग को ध्यान में रखकर औद्योगिक प्रयोजनों के लिए १०,००० एकड़ भूमि अधिसूचित करने का निर्णय लिया है ।

८. मेरी सरकार ने, औद्योगीकरण को बढ़ावा देने, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला कार्यक्षमता में सुधार लाने और विश्व स्तर कारोबार पारिस्थितिकी निर्माण करने के लिए १० एकीकृत औद्योगिक पार्क और एकीकृत मालपरिवहन पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है ।

९. मेरी सरकार ने, राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने के लिए "महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियान" शुरू करने के लिए अनुमोदन दिया है । वस्त्रोद्योग में अपने नेतृत्व को अधिक सुदृढ़ बनाते हुए केन्द्र के राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्रोद्योग मिशन से सुसंगत इस तरह का मिशन शुरू करनेवाला महाराष्ट्र, देश का प्रथम राज्य बना है ।

१०. मेरी सरकार ने, १४ से १७ फरवरी २०२५ तक, नई दिल्ली में भारत सरकार द्वारा आयोजित "भारत टेक्स-२०२५" इस वैश्विक कार्यक्रम में "ज्ञान भागीदारी राज्य" के रूप में भाग लिया था । इससे राज्य के वस्त्रोद्योग उत्पादों को वैश्विक बाजार तक

पहुँच पाने में मदद मिली है। इससे राज्य के वस्त्रोद्योग क्षेत्र में निवेश और रोज़गार के अवसर निर्माण होंगे।

११. मेरी सरकार ने, जालना जिले में रेशम कृमिकोश का क्रय और विक्रय करने तथा उस क्षेत्रों के रेशम कृमिकोश उत्पादक किसानों को समर्थन देने के लिए एक खुला बाजार स्थापित किया गया है। बाजार का संनिर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे, इस क्षेत्र में रेशम कृमिकोश उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।

१२. मेरी सरकार ने, राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्योगों के लिए कुशल श्रमशक्ति देने के लिए "मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत्, १ लाख ३२ हजार से अधिक युवा प्रशिक्षण ले चुके हैं। सरकार ने, वर्ष २०२४-२५ के लिए, १० लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है और इस प्रयोजन के लिये ५५०० करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

१३. मेरी सरकार ने, वर्ष २०२४-२५ में, बेरोजगार युवाओं को उद्योगों से जोड़ने और रोज़गार के अवसर निर्माण करने के लिए, संपूर्ण महाराष्ट्र में जिला स्तर पर ६११ "पंडित दीनदयाळ रोजगार मेळावे" आयोजित किए हैं। राज्य में इस वर्ष १९,००० से अधिक उम्मीदवारों ने नौकरियाँ प्राप्त की हैं।

१४. मेरी सरकार, गतिशील और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "त्रिसूत्री कार्यक्रम" का कार्यान्वयन कर रही है। यह कार्यक्रम सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना करने, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और एकीकृत मानव संसाधन प्रणाली विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

१५. मेरी सरकार ने, प्रशिक्षण के ज़रिए परिवर्तन लाने के लिए, "कर्मयोगी भारत कार्यक्रम" के तहत् आय-गॉट प्रणाली में लगभग पाँच लाख कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि, सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशासनिक विभागों को गतिशील और गुणवत्तापूर्ण कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रोत्साहित करने के लिए "सेवाकर्मी पुरस्कार कार्यक्रम" कार्यान्वित किया जाएगा।

१६. मेरी सरकार ने, नागपुर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती मार्ग का संनिर्माण कार्य हाथ में लेने का निर्णय लिया है। इस द्रुतगती मार्ग का संनिर्माण सबको विश्वास में लेकर ही पूरा किया जायेगा। यह द्रुतगती मार्ग रास्ते के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों को जोड़नेवाला होगा। यह द्रुतगती मार्ग न केवल यात्रा के समय को कम करेगा बल्कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत ८६,३०० करोड़ रुपए हैं।

१७. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में सड़कों की मजबूती बढ़ाने, सड़कों को जोड़ने में सुधार लाने और सुरक्षित तथा अधिक कार्यक्षम परिवहन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत् ७४८० किलोमीटर लंबाई की सीमेंट कंक्रीटीकरण की सड़कें संनिर्मित करने का निर्णय लिया है।

१८. मेरी सरकार ने, पथकर नाकाओं पर दक्षता बढ़ाने, भीड़ कम करने और डिजिटल संव्यवहार को बढ़ावा देने के लिए १ अप्रैल २०२५ से संपूर्ण राज्य के सभी पथकर नाकाओं पर केवल फास्टॅग के ज़रिए पथकर शुल्क लेने का निर्णय लिया है।

१९. केंद्र प्रायोजित "पीएम ई-बस सेवा योजना" के तहत् प्रथम चरण में २० नगर निगमों के लिए १२९० बसें मंजूर की गई हैं और इन नगर निगमों में बस आगारों को विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।

२०. मेरी सरकार ने, १ अप्रैल २०२५ से अगले तीन वर्षों के लिए नया "महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण" लागू करने का निर्णय लिया है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन देने और पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह राज्य के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और परिवहन को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है।

२१. मेरी सरकार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में, बेहतर बुनियादी ढ़ांचे के ज़रिए शहरी जीवनयापन में सुधार लाने के लिए "नगरोत्थान महाभियान" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वचनबध्द है। इस योजना के तहत् जल आपूर्ति, मल-जल-निकास और विकास के लिए चल रही परियोजनाओं को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

२२. मेरी सरकार ने, सार्वजनिक निजी भागीदारीता के ज़रिए पंप भंडारण परियोजना के कार्यान्वयन द्वारा विद्युत भंडारण और ग्रिड स्थिरता के लिए १३ अभिकरणों के साथ ३८ परियोजनाओं के लिए सहमति-पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन परियोजनाओं से ५५,९७० मेगा वॅट बिजली निर्माण होगी और उससे राज्य को २ लाख ९५ हजार करोड़ रुपयों का निवेश प्राप्त होने का अनुमानित है और ९०,००० से अधिक रोज़गार के अवसर निर्माण होंगे।

२३. मेरी सरकार ने राज्य के किसानों को सौर ऊर्जा से चलनेवाले पंपों के ज़रिए कृषि के लिए पानी मिलने में मदद करने के लिए "मागेल त्याला सौर पंप योजना" के तहत् ३,१२,००० सौर पंप बिठाए गए हैं। इस योजना के तहत् किसानों को अगले पाँच वर्षों में १० लाख सोलर पंप दिये जानेवाले है।

२४. "प्रधानमंत्री-कुसुम" और "मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना" इन योजनाओं के तहत् राज्य में सभी कृषि फीड़र को सौर ऊर्जाकृत करनेवाला देश का प्रथम राज्य बनाने का लक्ष्य महाराष्ट्र ने रखा है। केवल नौ महीने के रिकॉर्ड समय में १४७ मेगा वॅट क्षमता की संयुक्त सौर ऊर्जा क्षमतावाले कुल ११९ फीड़र कार्यान्वित किए गए हैं।

२५. मेरी सरकार, संपूर्ण राज्य के ४०९ शहरी समूहों में "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" लागू कर रही है। इस योजना के तहत् दो लाख से अधिक मकानों का संनिर्माण किया जा चुका है और १ लाख ८५ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण कार्य प्रगति पर है।

२६. मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण" के प्रथम चरण के तहत् राज्य में १२ लाख ६४ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण पूर्ण किया है। मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा २" के तहत् १६ लाख ८१ हजार से अधिक मकानों का संनिर्माण करने का निर्णय लिया है।

२७. मेरी सरकार, पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर संपूर्ण राज्य के २८ जिलो में ७७ पूर्ण समूह पहाड़ी ब्लॉकों और १०१ उप-समूह पहाड़ी ब्लॉकों में "डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम" कार्यान्वित कर रही है।

२८. मेरी सरकार ने, चालू वर्ष में "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" योजना के तहत् १२७४ जल स्त्रोतों से लगभग चार करोड़ घनमीटर गाद निकाली गयी है , जो ९५,००० एकड़ भूमि में फैली गई है, जिससे ३१,००० से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

२९. मेरी सरकार, "प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना" के तहत् आयोजित "वॉटरशेड यात्रा" के ज़रिए जलसंभर प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता निर्माण कर रही है और इसमें सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। जलसंभर यात्रा ८ फरवरी २०२५ से शुरू हुई है और वह ३१ मार्च २०२५ तक संपूर्ण राज्य के ३० जिलों की १४० परियोजनाओं में जानेवाली है।

३०. मेरी सरकार, सामुदायिक भागीदारी के ज़रिए शाश्वत भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में "अटल भूजल योजना" सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत्, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और अभिसरण घटक के लिए १३३६ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जिसमें १,३२,००० एकड़ से अधिक कृषि भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत् लाया गया है।

३१. मेरी सरकार ने, राज्य के कृषि क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं का उपयोग करनेवाले किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का जल्द और प्रभावी वितरण सुकर करने के लिए "ॲग्रीस्टॅक"- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत संरचना नामक एक नई योजना शुरू की है।

३२. मेरी सरकार ने, "प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना" के तहत् राज्य के ९५ लाख से अधिक किसानों को लाभार्थियों के रूप में चयनित किया गया है और ८७ लाख से अधिक किसानों को बैंकों द्वारा किसान क्रेड़िट कार्ड की सुविधा दी है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक सहायता और ऋण सुविधा देकर किसानों को सशक्त बनाना है।

३३. मेरी सरकार ने, किसानों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में ७४,७८१ करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरण करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को बैंकों के ज़रिए ५५,३३४ करोड़ रुपयों की राशि का वितरण किया गया है। मेरी सरकार, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है।

३४. मेरी सरकार ने, शाश्वत ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इथेनॉल का विकल्प ईंधन के रूप में उपयोग करने पर जोर देते हुए, इथेनॉल के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने की पहल की है। मेरी सरकार, वर्ष २०२४-२५ के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा तेल विपणन कंपनियों को १२१ करोड़ लीटर इथेनॉल आपूर्ति करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करेगी।

३५. मेरी सरकार ने, किसानों को राहत देने के लिए "किमान आधारभूत किंमत योजना" के तहत् वर्ष २०२४-२५ मौसम के लिए ५६२ खरीद केंद्रों के ज़रिए ११,२१,३८५ मेट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की है।

३६. मेरी सरकार ने, खरीफ़ विपणन मौसम २०२४-२५ के दौरान सात लाख मेट्रिक टन से अधिक धान और १७१ मेट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद की है।

३७. मेरी सरकार, प्रत्येक तालुका के लिए कम से कम एक अलग कृषि उपज बाजार समिति स्थापित करने के लिए "मुख्यमंत्री एक तालुका एक बाजार समिती योजना" कार्यान्वित कर रही है।

३८. मेरी सरकार ने, "डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना" के तहत् संवेदनशील गांवों में १०,००० से अधिक लाभार्थियों को व्यक्तिगत सौर ऊर्जा बाड़ा लगाने के लिए १५,००० रुपयों तक का अनुदान वितरित किया है। इससे बाघ परियोजना और संरक्षित क्षेत्रों के आसपास मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद मिलेगी।

३९. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मदद करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है। मेरी सरकार ने, सात लाख ८० हजार से अधिक किसानों को ८१४ करोड़ रुपयों की आर्थिक सहायता वितरित की है।

४०. मेरी सरकार ने, केंद्र प्रायोजित योजना "नमो ड्रोन दीदी" के तहत् वित्तीय वर्ष २०२४-२५ में राज्य की ३२५ महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि प्रयोजनों के लिए ड्रोन वितरित करने का निर्णय लिया है।

४१. मेरी सरकार ने, महिला श्रमशक्ति सहभागीता दर को बढ़ाने और शहरों में महिलाओं को किफ़ायती और सुरक्षित आवास देने के लिए, केंद्र सरकार की "भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष सहाय्य योजना २०२४-२५" के तहत् कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास संनिर्मित करने के लिए प्रस्तावित किया है।

४२. मेरी सरकार ने, महिलाओं के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाने के लिए अंगणवाडी सेविकाओं के लगभग १८,००० रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है ।

४३. मेरी सरकार ने, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनके योगदान के बारे में बच्चों को शिक्षित करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रत्येक वर्ष अंगणवाडी में "छत्रपति शिवाजी महाराज" जयंती मनाने का निर्णय लिया है ।

४४. मेरी सरकार, महिलाओं की घरेलू आय बढ़ाने के लिए, "लखपती दीदी" पहल कार्यान्वित कर रही है। अब तक, १७ लाख महिलाएँ अपनी घरेलू आय को एक लाख रुपये या उससे ऊपर तक ले जाने में सफल रही हैं। वर्ष२०२४-२५ के अंत तक, २६ लाख ग्रामीण महिलाओं को "लखपती दीदी" बनने के लिए सशक्त करने का लक्ष्य रखा है।

४५. मेरी सरकार ने, राज्य में विभिन्न समुदायों के उत्थान के लिए १८ निगम स्थापित किए हैं। इसके लिए, प्रत्येक निगम को ५० करोड़ रुपयों की शेयर पूंजी मंजूर की गई है।

४६. मेरी सरकार ने, सरकारी चिकित्सा और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अनुसूचित जनज़ातियों के छात्रों की अधिकतम संख्या में प्रवेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंजीनियरिंग और चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जनज़ातियों के छात्रों के लिए प्रशिक्षण वर्ग शुरू करने का निर्णय लिया है।

४७. मेरी सरकार ने, बीड़ जिले में परली और पूणे जिले में बारामती में सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

४८. मेरी सरकार ने, उच्च शिक्षा के अवसरों, छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक संसाधनों के बारे में कक्षा ९ वीं से १२ वीं तक के छात्रों में जागरूकता निर्माण करने के लिए “स्कूल कनेक्ट भाग २.०" शुरू किया है।इस पहल में, लगभग १२०० महाविद्यालयों, ४८०० विद्यालयों और १ लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया है।

४९. महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय मुल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (नॅक) द्वारा मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की सबसे उच्चतम संख्या होने से देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह उच्च शिक्षा मानकों में सुधार के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मेरी सरकार ने “राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति २०२०" कार्यान्वित की है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों का उपबंध करने के लिए मेरी सरकार, वचनबद्ध है।

५०. मेरी सरकार ने, नासिक की रामायण से जुड़ी विरासत को संरक्षित करने और इसे समग्र तीर्थस्थल में बदलने के लिए नासिक में राम-काल-पथ परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

५१. मेरी सरकार ने, महापे, नवी मुंबई में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कुशल श्रमशक्ति और संसाधनों से सुसज्जित "महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प" शुरू किया है। इस परियोजना से, जो सायबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सायबर अपराधों की जाँच करने में पुलिस कर्मियों को मदद होगी।

५२. मेरी सरकार ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत् राज्य में १० वर्षों तक सेवा दे चुके ठेका कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय लिया है। इन्हे स्वास्थ्य सेवा में मंजूर समकक्ष पदों पर समायोजित किया जायेगा।

५३. मेरी सरकार ने, केमोथेरेपी और रेडिओथेरेपी केंद्रों में कैंसर रोगियों पर उपचार करनेवाली कैंसरविज्ञान की कुशल परिचारिकाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन ऑन्कॉलॉजी नर्सिंग" पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हमारे स्वास्थ्यसेवा कर्मचारियों को मजबूत करने के लिए नासिक, सिंधुदुर्ग और सतारा जिलों में तीन नये बी.एससी. परिचारिका महाविद्यालय स्थापित किए जायेंगे।

५४. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र को चिकित्सा अनुसंधान और अभिनव पहल का केंद्र बनाने और उन्नत अनुसंधान और शिक्षा के ज़रिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के लिए "कॉंसोर्टिया फॉर हेल्थ, अप्लाइड नॉलेज अँड रिसर्च ऑटोनॉमी" नामक एक कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक के तहत् महाराष्ट्र स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था, यह केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जबकि सात अन्य सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय उपरोक्त अनुसंधान प्रयोजनों के लिए सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

५५. मेरी सरकार ने, संपूर्ण राज्य में रक्तदान मुहिम, अंग दान, कैंसर जागरूकता और उपचार, मोटापा जागरूकता और उपचार, थायरॉइड मुहिम, मोतीबिंदू-अंधापन रोकथाम मुहिम, मौखिक स्वास्थ्य मुहिम जैसी ७ स्वास्थ्य मुहिमों को शुरू किया है। इन विशेष मुहिमों के तहत् मार्च २०२५ तक लगभग एक लाख लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा।

५६. मेरी सरकार, हर व्यक्ति के दरवाजे तक, आयुर्वेद को पहुंचाने के लिए "देश का प्रकृती परीक्षण" यह मुहिम कार्यान्वित कर रही है। यह मुहिम स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने, तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने और प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की समय-परीक्षित उपचार पद्धतियों का प्रचार करती हैं। इस मुहिम के तहत्, ४० लाख से अधिक नागरिकों की जाँच की गई है और राज्य ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है।

५७. मेरी सरकार ने, ऑलिम्पिक समेत महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर छह उच्च प्रदर्शन केंद्र और ३७ विभागीय क्रीड़ा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए "मिशन लक्ष्यवेध" यह एक नई और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। यह १२ ऑलिम्पिक खेलों, अर्थात् एथलेटिक्स, बॅडमिंटन, मुष्टियुद्ध, भारोत्तोलन, हॉकी, कुश्ती, तिरंदाजी, नेमबाजी, रोईंग, नौकानयन, लॉन टेनिस और टेबल टेनिस पर ध्यान केंद्रित करेगी।

५८. मेरी सरकार ने, राज्य के खिलाड़ियों, विशेषकर विदर्भ के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय मानक क्रीड़ा सुविधाएं देने के लिए, बालेवाड़ी के राज्य स्तरीय क्रीड़ा संकुल की तरह नागपुर के विभागीय क्रीड़ा संकुल का दर्जा उन्नत करने का निर्णय लिया है।

५९. मेरी सरकार ने, भारत के संविधान को ७५ वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागरिकों में भारत के संविधान के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों और मूलभूत कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "घर-घर संविधान कार्यक्रम" शुरू किया है।

६०. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, केंद्र सरकार ने हाल ही में, मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है। मेरी सरकार, महाराष्ट्र की जनता की ओर से इस अच्छे कार्य के लिये माननीय प्रधानमंत्री श्री. नरेंन्द्र मोदीजी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करती है। तद्नुसार, मेरी सरकार ने, अभिजात मराठी भाषा दिन, अभिजात मराठी भाषा सप्ताह, अभिजात मराठी भाषा में अनुसंधान के क्षेत्र से प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान, अभिजात मराठी भाषा का इतिहास दर्शानेवाली एक डॉक्यूमेंट्री, उत्कृष्टता केंद्र और अनुवाद अकादमी की स्थापना जैसे कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है।

६१. मेरी सरकार, सभी समुदाय वर्गों को साथ लेकर एक सर्वसमावेशी, प्रगतिशील और विकसित महाराष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है।

माननीय सदस्यों, इस सत्र में नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव, विनियोग विधेयक और अन्य विधिविधान आपके विचारार्थ रखे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि, महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिये माननीय सदस्य कामकाज में भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार-विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे।

मैं फिर से एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद! जय महाराष्ट्र!!